5 सादगीपूर्ण जीवनशैली और अनुशासन

6 श्री खाटू श्याम जी मंदिर का भव्य भूमि पूजन

7 छोटी नदियां बचाओ, बड़ी नदियां संवरेगी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 42 प्रति सोमवार, 23 फरवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल, स्वस्थ और सशक्त भविष्य की आधारशिला है सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान

स्वस्थ बचपन–सशक्त मातृत्व सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान से बदलती विकास की तस्वीर

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने और वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत देखी है, जो केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का व्यापक आह्वान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ "सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान" राज्य के भविष्य के बच्चों और माताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया एक सशक्त और संवेदनशील प्रयास है। यह पहल स्पष्ट करती है कि सरकार विकास को केवल सड़क, भवन और उद्योगों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि मानव संसाधन के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

संवेदनशील सोच और ठोस शुरुआत

1 जनवरी 2026 से प्रदेश के आठ संवेदनशील जिलों बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक साथ इस अभियान की शुरुआत करना स्वयं में दूरदर्शी निर्णय है। ये वे क्षेत्र हैं जहां भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां अधिक हैं। ऐसे इलाकों को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास की मुख्यधारा में सबसे पहले उन लोगों को जोड़ा जाएगा, जो अब तक हाशिए पर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी राज्य का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य और माताओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। उनका यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वे प्रशासन को केवल प्रबंधन नहीं, बल्कि मानवीय दायित्व के रूप में देखते हैं। कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से लड़ाई को उन्होंने नीति और संवेदना, दोनों के स्तर पर प्राथमिकता दी है। (शेष पेज 2 पर)

■ मप्र बजट 2026-27

बदहाल आर्थिक हालात के बीच बजट में सभी को साधने की कोशिश

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। साढ़े चार लाख करोड़ से अधिक रूपये के भारी भरकम बजट में सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन बजट में केवल घोषणाएं भर दिख रही है। इन पर राशि कहां से आयेगी और कैसे आयेगी इस पर संशय बरकरार है। यही कारण है कि बजट को विपक्ष ने हास्यापद बताया है। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। बजट भाषण लंबा था, आंकड़े भारी-भरकम थे और घोषणाओं की चमक ऐसी कि जैसे हर समस्या का समाधान अगले वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से ही मिलने वाला हो।

(शेष पेज 2 पर)

एक पेड़ माँ के नाम अभियान और लाखों पेड़ों की कटाई: कैसे बचेंगे जंगल?

सिंगरौली में गौतम अडानी को दी 06 लाख पेड़ काटने की परमीशन!

-विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान की शुरुआत की थी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान मां के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडानी समूह को धिरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,672 हेक्टेयर (लगभग 6,600+ एकड़) वन और निजी भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना के कारण लगभग 06 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई करने की परमीशन दी है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी को लाखों पेड़ काटने की परमीशन दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की यह दोहरी नीति लोगों को रास नहीं आ रही है। सिंगरौली का यह 2,672 हेक्टेयर कुल क्षेत्र है, जिसमें 1,397 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि शामिल है। परियोजना के लिए लगभग 6 लाख से 10 लाख पेड़ काटे जाने की आशंका है। अडानी की धीरौली खदान की उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तय की गई है। इसमें से 05 मिलियन टन कोयला खुली खदानों से और शेष उत्पादन भूमिगत खनन से निकाला जाएगा। इस ब्लॉक में कुल 620 मिलियन मीट्रिक टन सकल भू-गर्भीय भंडार मौजूद है। वहीं, शुद्ध भंडार 558 मिलियन मीट्रिक टन है। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक खुली खदान की अधिकतम क्षमता हासिल कर ली जाए। (शेष पेज 3 पर)

मध्यप्रदेश में 'शिक्षा माफिया' का चेहरा डॉ. सुनील कपूर, आरकेडीएफ समूह पर बढ़ता शिकंजा पढ़ें पेज 3 पर

बदहाल आर्थिक हालात के बीच बजट में सभी को साधने की कोशिश

(पेज 1 का शेष)

लेकिन जमीन पर खड़े आम नागरिक की जेब टटोलिए, तो उसे अभी भी रसीदें ज्यादा और राहत कम ही मिलती है। सरकार ने बजट को "विकास का विजन डॉक्यूमेंट" बताया। सड़कों के जाल, निवेश के भव्य सपने, युवाओं के लिए अवसरों की बौछार और किसानों के लिए योजनाओं की नई फसल सब कुछ कागज पर सुव्यवस्थित दिखता है। मगर जनता को यह समझ नहीं आता कि हर साल योजनाएँ इतनी नई क्यों होती हैं और पुरानी योजनाएँ अचानक स्मृति-लेख का हिस्सा कैसे बन जाती हैं। घोषणाओं की खेती इतनी लहलहाती है कि असल खेत में खड़े किसान को समर्थन मूल्य और मौसम की मार से राहत के लिए फिर भी संघर्ष करना पड़ता है।

युवाओं के लिए कौशल, स्टार्टअप और रोजगार की बातें सुनने में आकर्षक लगती हैं। परंतु नौकरी की तलाश में शहर-दर-शहर भटकते डिग्रीधारी युवक से पूछिए तो वह कहेगा कि बजट में अवसरों की संख्या और भर्ती विज्ञापनों की संख्या का अनुपात अभी भी गणित का अनसुलझा सवाल है। कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र खुलते हैं, प्रमाणपत्र मिलते हैं, मगर नियुक्ति पत्र का इंतजार अब भी लंबी कतार में खड़ा है। महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणाएँ भी कम नहीं रहीं। सशक्तिकरण के नाम पर सहायता राशि, समूहों को प्रोत्साहन और सुरक्षा के आश्वासन सब कुछ शामिल है। पर सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से हर पात्र महिला तक पहुँचेगा? या फिर आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया में कई लाभार्थी आधे रास्ते में ही थक जाएंगे? सशक्तिकरण का अर्थ केवल राशि वितरण नहीं, बल्कि स्थायी अवसर और संरचनात्मक बदलाव भी होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों हैं। भवन बन जाने से शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ती और मशीनें आ जाने से इलाज सुलभ नहीं हो जाता। असली चुनौती व्यवस्था के संचालन और जवाबदेही की है, जिसका जिक्र भाषणों में कम और अनुभवों में अधिक मिलता है।

शहरी विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएँ और आधारभूत संरचना पर खर्च का वादा किया गया है। किंतु छोटे शहरों की टूटी सड़कों, जल निकासी की समस्याओं और अनियमित जलापूर्ति से जूझते नागरिकों को यह समझाना कठिन है कि विकास की गंगा उनके मोहल्ले तक कब पहुँचेगी। राजधानी में चमकते फ्लाई ओवर और जिलों में जाम से जूझती गलियाँ यह विरोधाभास अब भी कायम है। राजकोषीय अनुशासन और संतुलित वित्त प्रबंधन की बात भी जोर-शोर से की गई। लेकिन जनता का सरोकार सरल हैमहंगाई कम होगी या नहीं? बिजली-पानी के बिल में राहत मिलेगी या नहीं? करों का बोझ घटेगा या नहीं? बजट भाषण इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर कम और परोक्ष संकेत अधिक देता है। दरअसल, हर बजट उम्मीदों का दस्तावेज होता है। सरकार उसे उपलब्धियों का रोडमैप बताती है और विपक्ष उसे वादों की पुनरावृत्ति कहता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जनता को हाथ में तुरंत कुछ ठोस नहीं दिखता, पर उसे भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य उज्ज्वल है। यही "भविष्य" हर साल थोड़ा और आगे खिसक जाता है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

किसानों को 01 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे

3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।

श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान

श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं।

कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट

सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को सौगात

इस बजट में महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने नारी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 07 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के विकास के लिए 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़

मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए "संध्या छाया" प्रोग्राम शुरू किया गया है।

पीएम आवास के लिए 06 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

06 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ का प्रावधान

कृषि वानिकी योजना शुरू की जाएगी, इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 06 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 3,60 हजार करोड़

सिंहस्थ आयोजन की तैयारियों के लिए अब तक 13 हजार 851 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ के लिए 03 हजार 60 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल, स्वस्थ और सशक्त भविष्य की आधारशिला है सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान

(पेज 1 का शेष)

कुपोषण मुक्त बचपन की ओर निर्णायक कदम

"सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान" का मूल उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना और 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं विशेषकर गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया की समस्या को प्रभावी रूप से कम करना है। यह लक्ष्य केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि पीढ़ियों के स्वास्थ्य का प्रश्न है। कुपोषण केवल शारीरिक कमजोरी का विषय नहीं होता, यह बच्चों के मानसिक विकास, शिक्षा, उत्पादकता और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने इस तथ्य को समझते हुए पोषण को राज्य के विकास एजेंडे का अभिन्न अंग बनाया है। आने वाले छह महीनों में रक्ताल्पता की दर में उल्लेखनीय कमी लाने और गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं। यह लक्ष्य-आधारित कार्यप्रणाली प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधनः सहभागिता का मॉडल

इस अभियान की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम। यह दृष्टिकोण बताता है कि सरकार ने समस्या को केवल ऊपर से नीचे तक लागू होने वाली योजना के रूप में नहीं देखा, बल्कि समुदाय को साझेदार बनाया है। गंभीर (SAM) और मध्यम (MAM) कुपोषित बच्चों, संकटग्रस्त बच्चों और चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष हस्तक्षेपों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि सबसे अधिक जरूरतमंद वर्गों तक लक्षित सहायता पहुंचे। "सुपोषण दूत" की अवधारणा इस अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देती है। 70 प्रतिशत मध्यम और 30 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करना, केवल प्रशासनिक उपाय नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का विस्तार है। बच्चों को सामान्य पोषण स्तर में लाने पर सुपोषण दूतों को प्रोत्साहन राशि देना एक प्रेरक मॉडल है, जो सेवा और परिणाम दोनों को जोड़ता है। इसी प्रकार महिला स्व-सहायता समूहों को भी कुपोषित बच्चों की देखभाल से जोड़ना, महिलाओं को सशक्त बनाने और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर जागरूकता, निगरानी और जवाबदेही मजबूत होगी।

पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही

किसी भी योजना की सफलता उसकी सतत निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। स्थानीय निधि से कुपोषित बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम चाहती है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूह और समुदायसभी को एक समन्वित ढांचे में जोड़ना एक सशक्त प्रशासनिक दृष्टि का परिचायक है।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता

मातृत्व को सशक्त किए बिना स्वस्थ समाज की कल्पना अधूरी है। गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया की समस्या को कम करने का स्पष्ट लक्ष्य तय करना इस दिशा में निर्णायक पहल है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार से नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे दीर्घकालिक रूप से कुपोषण की श्रृंखला टूटती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का जो संकल्प लिया है, वह आने वाले वर्षों में प्रदेश की मानव विकास सूचकांकों में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। यह पहल छत्तीसगढ़ को केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाली है।

सामाजिक आंदोलन की ओर अग्रसर

"सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान" अब केवल एक विभागीय कार्यक्रम नहीं रहा, यह जनसहयोग और सामुदायिक सहभागिता से व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। जब सरकार और समाज मिलकर किसी समस्या से लड़ने का संकल्प लेते हैं, तब परिणाम स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य केवल आंकड़ों में सुधार दिखाना नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक माता तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना ही इस अभियान की आत्मा है।

दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान

किसी भी राज्य का नेतृत्व तब प्रभावी माना जाता है, जब वह तात्कालिक राजनीतिक लाभ से आगे बढ़कर दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करे। सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह पहल बताती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केवल प्रशासन चला नहीं रहे, बल्कि भविष्य गढ़ रहे हैं। स्वस्थ बचपन और सशक्त मातृत्व की दिशा में उठाया गया यह कदम आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को नई पहचान देगा। यदि अभियान अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो यह न केवल कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध निर्णायक परिणाम देगा, बल्कि राज्य को मानव विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। "सुपोषित छत्तीसगढ़" केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक संकल्प हैऐसा संकल्प जो हर बच्चे की मुस्कान और हर माता के आत्मविश्वास में झलकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह पहल छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल, स्वस्थ और सशक्त भविष्य की आधारशिला बनती दिख रही है।

मध्यप्रदेश में 'शिक्षा माफिया' का चेहरा डॉ. सुनील कपूर, आरकेडीएफ समूह पर बढ़ता शिकंजा

मार्कशीट, मान्यता और मनी ट्रेल: आरकेडीएफ समूह व डॉ. सुनील कपूर पर बढ़ती जांच की परतें

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि कुछ निजी संस्थान सेवा नहीं, बल्कि मुनाफे का जरिया बना चुके हैं। हालिया घटनाक्रमों ने इन आरोपों को और गहरा किया है। आरकेडीएफ समूह और उसके प्रमुख डॉ. सुनील कपूर का नाम बार-बार विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आना इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला केवल प्रशासनिक चूक तक सीमित नहीं, बल्कि एक संगठित शैक्षणिक घोटाले की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

एक बड़े खुलासे की आहट

राजस्थान पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा भोपाल स्थित आरकेडीएफ विश्वविद्यालय परिसरों और संस्थान के निदेशक सुनील कपूर के आवास पर की गई छापेमारी ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। यह कार्रवाई कथित तौर पर फर्जी या अनियमित मार्कशीट जारी किए जाने की जांच के सिलसिले में की गई। एसटीएफ की टीमें एक साथ आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के गांधीनगर और नर्मदापुरम रोड स्थित परिसरों में दाखिल हुईं, जबकि एक अलग टीम डॉ. कपूर के आवास पर पहुंची। एसटीएफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी मार्कशीट या दस्तावेज जारी किए गए।

अंतरराज्यीय जांच और पुराने मामलों की कड़ियाँ

यह कार्रवाई केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला कई राज्यों में फैले एक व्यापक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। यही कारण है कि इसे एक अंतरराज्यीय जांच का रूप दिया गया है। आरकेडीएफ समूह से जुड़े विवाद कोई नए नहीं हैं। दिसंबर 2015 में मध्यप्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ने आरकेडीएफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को दी गई रियायतों में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। उस समय भी आरोप लगे थे कि नियमों को ताक पर रखकर संस्थान को लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, डॉ. सुनील कपूर का नाम तेलंगाना में भी कानूनी जांच के दायरे में आया। आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्रियां जारी करने के आरोप में

उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और तेलंगाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। यह घटनाक्रम इस ओर संकेत करता है कि कथित शैक्षणिक धोखाधड़ी का दायरा राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।

90 करोड़ रुपये का कथित घोटाला

लगभग 15 वर्ष पहले राजस्थान एसटीएफ की कार्रवाई से पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो डॉ. सुनील कपूर और उनसे जुड़े संस्थानों पर शिकंजा कस चुकी है। सीबीआई ने प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य डॉ. कपूर के आवास और आयुष्मती सोशल सोसायटी द्वारा संचालित चार इंजीनियरिंग कॉलेजों पर एक साथ छापेमारी कर लगभग 90 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के तहत सत्य साईं अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भी छापा मारा गया, जिसकी अध्यक्ष डॉ. कपूर की मां बताई जाती हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, छापेमारी आठ स्थानों पर की गई, जिनमें आरकेडीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज, सत्य साईं इंजीनियरिंग कॉलेज, भाभा इंजीनियरिंग कॉलेज, भाभा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और आयुष्मती सोशल सोसायटी के पदाधिकारियों के आवास शामिल थे।

फर्जी एफडीआर और मान्यता का खेल

जांच में सामने आया कि आयुष्मती सोशल सोसायटी ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से इंजीनियरिंग कॉलेजों की मान्यता प्राप्त करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये मूल्य की 35 फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (एफडीआर) प्रस्तुत कीं। कुल मिलाकर यह राशि करीब 87.5 करोड़ रुपये बैठती है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस बैंक के माध्यम से ये एफडीआर तैयार की गईं, उसमें वास्तविक जमा राशि केवल 10 लाख रुपये बताई गई। आरोप है कि बैंक के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर धनराशि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, ताकि नियामक संस्थाओं को गुमराह किया जा सके। यह घोटाला इस वर्ष जुलाई में आरकेडीएफ कॉलेज और सत्य साईं अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की गहन जांच शुरू की।

प्रसार भारती बोर्ड की सदस्यता और नैतिक सवाल

डॉ. सुनील कपूर का नाम केवल एक शिक्षाविद या संस्थान प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सामने आता है। ऐसे में जब उन पर गंभीर वित्तीय और शैक्षणिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की छवि का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों की साख पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह शिक्षा क्षेत्र में नियामक तंत्र की विफलता को भी उजागर करेगा। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कथित फर्जीवाड़ा वर्षों तक कैसे चलता रहा और संबंधित एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?

शिक्षा माफिया की परिभाषा और हकीकत

'शिक्षा माफिया' शब्द अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में सुनने को मिलता है, लेकिन आरकेडीएफ समूह से जुड़े मामलों ने इस शब्द को एक ठोस संदर्भ दिया है। जब शिक्षा संस्थानों का उपयोग डिग्री, मार्कशीट और मान्यता को एक व्यापारिक वस्तु की तरह करने के लिए किया जाए तो यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य और समाज की नींव के साथ खिलवाड़ है। डॉ. कपूर के खिलाफ चल रही विभिन्न एजेंसियों की जांचें अभी निर्णायक चरण में नहीं पहुंची हैं। बार-बार सामने आ रहे आरोप, छापेमारी और एफआईआर यह जरूर संकेत देते हैं कि मामला साधारण नहीं है। राजस्थान एसटीएफ, सीबीआई, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूत आने वाले समय में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। यह भी उम्मीद की जा रही है कि जांच एजेंसियां अपने निष्कर्ष शिक्षा नियामकों और राज्य पुलिस बलों के साथ साझा करेंगी, ताकि भविष्य में इस तरह के कथित घोटालों पर रोक लगाई जा सके। देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी कार्रवाई हो।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान और लाखों पेड़ों की कटाई: कैसे बचेंगे जंगल?

(पेज 1 का शेष)

जबकि भूमिगत खनन लगभग 09 साल बाद शुरू किया जाएगा। अदानी पॉवर को यह ब्लॉक 30 साल के पट्टे पर दिया गया है। अदानी पावर कंपनी के पास फिलहाल 1,200 मेगावॉट क्षमता वाला बिजली संयंत्र है। योजना है कि आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 3,200 मेगावॉट किया जाए। इसके लिए धौरैली खदान से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहां कई बड़ी कोयला खदानें और बिजली संयंत्र पहले से सक्रिय हैं। 03 मार्च 2021 को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद से इस पर विवाद जारी है। स्थानीय आदिवासियों की जमीन और आजीविका (महुआ, तेंदू, जलाऊ लकड़ी) पर संकट का आरोप लग रहा है।

सवाल यह नहीं कि जंगल क्यों कटे

सवाल यह है कि किसकी अनुमति से, किसकी चुप्पी से यह सब हुआ? आज सिंगरौली पूछ रहा है, क्या आदिवासी इंसान नहीं हैं? क्या उनका जंगल, उनकी जमीन सिर्फ कागज पर है? सरकार ने 204 करोड़ रुपये में पूरा जंगल अडानी को सौंप दिया, जबकि वहां 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कोयला है।

आवसीजन का बैंक रहे हैं सिंगरौली के जंगल

सिंगरौली जिले के अत्यंत पिछड़े विकासखंड देवसर में 1400 हेक्टेयर वन भूमि को अड़ानी समूह को कोयला उत्खनन के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया। लगभग 06 लाख पेड़ जो अधिकतर साल प्रजाति के हैं उनकी कटाई शुरू हो गई और अब तक 40,000 हजार पेड़ों को काट दिया गया है। साल के साथ, महुआ, चिरौंजी, आंवला, तेंदू, बीजा, बहेड़ा हर प्रजाति के वृक्ष जो स्थानीय आदिवासी, वनवासी समुदाय के आजीविका का मुख्य साधन है। यह हजारों वर्षों से अनवरत जारी था। अचानक आदेश से खत्म किया जा रहा है। सिंगरौली के जंगल अनादिकाल से विंध्य के ऑक्सीजन बैंक रहे हैं।

जंगल-जमीन खत्म कर बना रहे अडानी देशः जीतू पटवारी

आदिवासी परिवारों से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि '10 हजार एकड़ भूमि पर जल-जंगल-जमीन खत्म कर एक नया अडानी देश बनाया जा रहा है। बिना किसी पर्यावरण, शासन या सामाजिक अनुमति के जंगल को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। आदिवासियों और स्थानीय लोगों को न मुआवजा मिला, न ही कोई पुनर्वास। जीतू पटवारी ने कहा कि यह कदम राज्य के 1.5 करोड़ आदिवासियों के अधिकारों पर हमला है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा, "मां के नाम पर एक पेड़ और अडानी के नाम पर लाखों पेड़," यह मोदी सरकार के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। पिछले दिनों कांग्रेस की 12 सदस्यीय टीम सिंगरौली पहुंची थी।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सिंगरौली के आदिवासियों ने थी मुलाकात

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के आदिवासियों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान आदिवासियों ने अपनी जमीनी समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर राहुल-प्रियंका ने सिंगरौली आने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वन एवं वनवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक पैसा एक्ट और वनाधिकार अधिनियम लाए परंतु इस बबर सत्ता ने इसे धीरौली के इकोसिस्टम, जैव विविधता और आदिवासी-वनवासी समुदाय को लाभ और सुरक्षा ना पहुंचे इसका पूरा प्रबंध किया। आदिवासियों ने उनके समक्ष अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में औद्योगिक गतिविधियों और खनन परियोजनाओं के कारण वह लंबे समय से विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बढ़ सकती हैं अडानी की मुसीबतें

अडानी ने अमेरिका में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड पर अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। मामला 20 नवंबर 2024 के उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया था कि 2020 से 2024 के बीच सोलर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत दी गई। अमेरिका पिछले 14 महीने से अडानी को समन देना चाहता है, इसके लिए मोदी सरकार से मदद मांगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को समन भेजने नहीं दे रहे हैं। आखिर अडानी को लेकर मोदी सरकार फेवर में क्यों रहती है। जबकि अडानी के कारण देश की काफी किरकिरी हो रही है। इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग आपराधिक जांच कर रहा है, जबकि SEC गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO विनीत जैन के खिलाफ सिविल केस चला रहा है।

सम्पादकीय

मप्र बजट: आख़िर जनता के हाथ क्या लगा?

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने जब विधानसभा में अपना बजट पेश किया तो सत्ता पक्ष की मेजें थपथपाहट से गूंज उठीं और विपक्ष के चेहरे पर वही पुराना सवाल तैर गया "आख़िर जनता के हाथ क्या लगा?" बजट भाषण लंबा था, आंकड़े भारी-भरकम थे, और घोषणाओं की चमक ऐसी कि जैसे हर समस्या का समाधान अगले वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से ही मिलने वाला हो। लेकिन जमीन पर खड़े आम नागरिक की जेब टटोलिए, तो उसे अभी भी रसीदें ज्यादा और राहत कम ही मिलती है। सरकार ने बजट को "विकास का विजन डॉक्यूमेंट" बताया। सड़कों के जाल, निवेश के भव्य सपने, युवाओं के लिए अवसरों की बौछार और किसानों के लिए योजनाओं की नई फसल सब कुछ कागज पर सुव्यवस्थित दिखता है। मगर जनता को यह समझ नहीं आता कि हर साल योजनाएँ इतनी नई क्यों होती हैं और पुरानी योजनाएँ अचानक स्मृति-लेख का हिस्सा कैसे बन जाती हैं। घोषणाओं की खेती इतनी लहलहाती है कि असल खेत में खड़े किसान को समर्थन मूल्य और मौसम की मार से राहत के लिए फिर भी संघर्ष करना पड़ता है।

युवाओं के लिए कौशल, स्टार्टअप और रोजगार की बातें सुनने में आकर्षक लगती हैं। परंतु नौकरी की तलाश में शहर-दर-शहर भटकते डिग्रीधारी युवक से पूछिए, तो वह कहेगा कि बजट में अवसरों की संख्या और भर्ती विज्ञापनों की संख्या का अनुपात अभी भी गणित का अनसुलझा सवाल है। कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र खुलते हैं, प्रमाणपत्र मिलते हैं, मगर नियुक्ति पत्र का इंतजार अब भी लंबी कतार में खड़ा है। महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणाएँ भी कम नहीं रहीं। सशक्तिकरण के नाम पर सहायता राशि, समूहों को प्रोत्साहन और सुरक्षा के आश्वासन सब कुछ शामिल है। पर सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से हर पात्र महिला तक पहुँचेगा? या फिर आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया में कई लाभार्थी आधे रास्ते में ही थक जाएंगे? सशक्तिकरण का अर्थ केवल राशि वितरण नहीं, बल्कि स्थायी अवसर और संरचनात्मक बदलाव भी होता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों हैं। भवन बन जाने से शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ती और मशीनें आ जाने से इलाज सुलभ नहीं हो जाता। असली चुनौती व्यवस्था के संचालन और जवाबदेही की है, जिसका जिक्र भाषणों में कम और अनुभवों में अधिक मिलता है।

शहरी विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएँ और आधारभूत संरचना पर खर्च का वादा किया गया है। किंतु छोटे शहरों की टूटी सड़कों, जल निकासी की समस्याओं और अनियमित जलापूर्ति से जूझते नागरिकों को यह समझाना कठिन है कि विकास की गंगा उनके मोहल्ले तक कब पहुँचेगी। राजधानी में चमकते फ्लाई ओवर और जिलों में जाम से जूझती गलियाँ यह विरोधाभास अब भी कायम है। राजकोषीय अनुशासन और संतुलित वित्त प्रबंधन की बात भी जोर-शोर से की गई। लेकिन जनता का सरोकार सरल है महंगाई कम होगी या नहीं? बिजली-पानी के बिल में राहत मिलेगी या नहीं? करों का बोझ घटेगा या नहीं? बजट भाषण इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर कम और परोक्ष संकेत अधिक देता है। दरअसल, हर बजट उम्मीदों का दस्तावेज होता है। सरकार उसे उपलब्धियों का रोडमैप बताती है और विपक्ष उसे वादों की पुनरावृत्ति कहता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जनता को हाथ में तुरंत कुछ ठोस नहीं दिखता, पर उसे भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य उज्ज्वल है। यही "भविष्य" हर साल थोड़ा और आगे खिसक जाता है।

सियासी गहमागहमी

आख़िर हेमंत कटारे के इस्तीफ़े की वजह क्या है?

राजनीति में यह सवाल जितना सीधा दिखता है, जवाब उतना ही गोलमोल निकलता है। कहा जा रहा है कि यह "नैतिकता" का फैसला है। भारतीय राजनीति में नैतिकता अचानक सक्रिय हो जाए, तो जनता को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य होता है आख़िर ऐसा कौन-सा ग्रहण लग गया कि कुर्सी खुद ही हल्की लगने लगी? इस्तीफ़े की वजहें कई बताई जा रही हैं व्यक्तिगत कारण, राजनीतिक रणनीति, संगठन की प्राथमिकताएँ, या फिर भविष्य की बड़ी चाल। राजनीति में त्याग भी अक्सर निवेश की तरह होता है। आज छोड़ा, कल कहीं बड़ा पाया। हो सकता है यह कदम "त्याग की छवि" गढ़ने का हो, ताकि अगली पारी और मजबूत तरीके से खेली जा सके। जनता के लिए यह घटनाक्रम वैसा ही है जैसे किसी धारावाहिक में अचानक मोड़ आ जाए कारण बाद में पता चलेगा, फिलहाल सस्पेंस बनाए रखिए। राजनीति में इस्तीफा अंत नहीं, अक्सर नई पटकथा की शुरुआत होता है।

मोहन यादव की अडानी के ऊपर मेहरबानी क्या वजह है?

क्या सच में अडानी को बिजली प्लांट के लिए भाजपा की मोहन सरकार ने सवा लाख करोड़ रुपये देने का वादा किया? सवाल बड़ा है, रकम उससे भी बड़ी और राजनीति का मंच हमेशा की तरह गर्म। आंकड़ा सुनते ही आम आदमी की आँखें चौड़ी हो जाती हैं उसे याद आता है कि उसकी बिजली का बिल समय पर न भरे तो नोटिस तुरंत आ जाता है, मगर सवा लाख करोड़ की चर्चा "विकास" के नाम पर बड़े आराम से हो जाती है। सरकार कहेगी यह निवेश है, प्रदेश के भविष्य में पूंजी का संचार है, रोजगार के अवसर हैं, उद्योग का विस्तार है। विपक्ष कहेगा यह दोस्ती का फल है, जनता की जेब से निकली संभावनाओं का निजीकरण है। सच शायद फाइलों के मोटे पन्नों और शर्तों की बारीक लाइनों में छिपा होगा, जिन्हें आम नागरिक शायद ही कभी पढ़ पाए। जब भी रकम बहुत बड़ी होती है, उसे "दीर्घकालिक लाभ" कहकर पेश किया जाता है। जनता बस इतना जानना चाहती है। इस सौदे से उसकी बिजली सस्ती होगी या नहीं? अगर जवाब गोलमोल है, तो सवाल और तेज होंगे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

PM ने समझौता कर लिया है।
उनका धोखा अब सामने आ गया है।

वे फिर से बातचीत नहीं कर सकते।
वे फिर से सरेंडर कर देंगे।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन भोपाल में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे है।यह सारी गुंडागर्दी सरकार के संरक्षण में चल रही है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था खुद सरकार ही ध्वस्त कर रही है। इन गुंडो पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

मोहसिना किदवई : सादगीपूर्ण जीवनशैली और अनुशासन ने जनता के बीच विश्वसनीय बनाया

समता पाठक/जगत प्रवाह

मोहसिना भारतीय राजनीति की उन सशक्त और गरिमामयी हस्तियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को सेवा, सादगी और सिद्धांतों के साथ जिया। उनका जीवन परिचय केवल राजनीतिक उपलब्धियों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की प्रेरक यात्रा है जिसने पुरुष-प्रधान राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। मोहसिना किदवई का जन्म 1 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें शिक्षा और सामाजिक मूल्यों का वातावरण मिला। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था से ही समाजसेवा की ओर झुकाव दिखाया। यही झुकाव आगे चलकर उन्हें सक्रिय राजनीति की राह पर ले गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ीं और संगठन में अपनी सक्रियता, स्पष्ट वक्तव्य शैली तथा जनसंपर्क क्षमता के कारण शीघ्र ही पहचान बनाने लगीं। उस दौर में जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, मोहसिना किदवई ने साहस और आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं और कई बार विधायक चुनी गईं। उनका राजनीतिक कद तब और बढ़ा जब उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जनहितकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। वे अपने शांत स्वभाव, संतुलित निर्णय और कार्य के प्रति निष्ठा के लिए जानी जाती रहीं।

मोहसिना किदवई का संसदीय जीवन भी अत्यंत उल्लेखनीय रहा। वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रहीं। संसद में उनकी उपस्थिति हमेशा गरिमामय और प्रभावशाली मानी जाती थी। वे मुद्दों पर तथ्यों और तर्कों के साथ बोलती थीं तथा सदन की मर्यादा का विशेष ध्यान रखती थीं। उनकी राजनीतिक यात्रा कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजरी। देश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं और संगठनात्मक मामलों में उनका अनुभव मार्गदर्शक माना जाता है।

मोहसिना किदवई का जीवन केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रसार के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे उन नेताओं में हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव प्राथमिकता दी। एक मुस्लिम महिला नेता के रूप में उन्होंने सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया और यह साबित किया कि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकती है। उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली और अनुशासन ने उन्हें जनता के बीच विश्वसनीय बनाया। वे आज भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं।

मोहसिना किदवई का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, समर्पण और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है। उन्होंने न केवल अपने परिवार या क्षेत्र का नाम रोशन किया, बल्कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को भी नई दिशा दी।

जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया, जिसमें पानी के उपयोग को प्रसाद के समान मानते हुए जल के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में "जल संचय-जन भागीदारी 2.0" अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभियान के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा विभिन्न जिलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले। पहले चरण में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर बोरवेल रिचार्ज, रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और ओपनवेल रिचार्ज जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 5 क्रिटिकल और 21 सेमी-क्रिटिकल भू-जल ब्लॉक चिन्हित हैं। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में इनमें से 5 ब्लॉकों में भू-जल निकासी में कमी और भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण "जल संचय-जन भागीदारी 2.0" के अंतर्गत तकनीक आधारित और अधिक परिणाममूलक रणनीति अपनाई जा रही है। राज्य सरकार ने 31 मई 2026 तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे जल सुरक्षा की दिशा में प्रदेश का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष पहल के तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले चार लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ-साथ औद्योगिक समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन डबरियों से भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सिंचाई एवं मछली पालन जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनकल्याणकारी अभियानों को मिल रही नई गति

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इन जनसेवा कैंपों के माध्यम से आमजन को विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट संदेश है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि "सरकार जनता के द्वार" की अवधारणा को भी साकार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर जनहित और सुशासन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

स्कॉर्पियो कार सहित 100 पाव देसी शराब के किए जप्त,एक आरोपी गिरफ्तार

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। नगर में शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बावजूद फिर शराब माफिया सक्रिय हुए हैं जो नर्मदापुरम नगर के आजू-बाजू के क्षेत्र से शराब नर्मदापुरम में सप्लाई करने का कार्य कर रहे हैं।

आबकारी विभाग ने ऐसी ही सूचना पर स्कॉर्पियो कार को देसी मदिरा के साथ जप्त करने में सफलता हासिल की है। आबकारी टीम अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि जप्त की गई शराब किस शराब ठेकेदार ने नर्मदापुरम में बेचने के लिए उपलब्ध कराई है। अवगत हो कि कलेक्टर सोनिया मीना के अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा नर्मदापुरम शहर में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर गैराज लाइन तिराहा क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान एक स्कॉर्पियो कार से देशी मदिरा प्लेन की कुल 100 पाव (लगभग 02 पेटी) जप्त की गई। अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त चार पहिया वाहन सहित मदिरा को जप्त कर आरोपी सलमान के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अहिरवार, आबकारी उपनिरीक्षक हेमंत चौकसे, आबकारी मुख्य आरक्षक दुर्गाप्रसाद मांझी, रघुवीर प्रसाद निमोदा, धर्मेंद्र वारंग, सुरेश नगर सैनिक रामोतार यादव एवं संतोष शुक्ला सम्मिलित रहे।

सांप्रदायिक जमात को जनता द्वारा नकारा जाना भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बढ़िया संदेश: अजय खरे

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रीवा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी साम्प्रदायिक जमात की हार का भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अच्छा संदेश है लेकिन बांग्लादेश में प्रमुख राजनीतिक दल आवामी लीग को प्रतिबंधित करके चुनाव से वंचित रखा जाना वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। 12 फरवरी को मत पत्र के जरिए जातीय संसद की 300 सीटों के लिए संपन्न हुए चुनाव परिणाम दूसरे दिन 13 फरवरी को ही आ गए। जिसमें बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया और वहीं साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही कट्टरपंथी जमात-ए- इस्लामी के सत्ता पाने के मंसूबे बुरी तरह बिखर गए। श्री खरे ने कहा कि भारत में भी चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए जिससे कई चरणों में चलने वाले मतदान को एक दिन में पूरा कराया जा सके। खरे ने बताया कि सीमा से लगे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए सन 2021 में ईवीएम के जरिए हुए चुनाव आठ चरणों में 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल तक एक माह से भी अधिक समय तक चले थे।

मतगणना 2 मई 2021 को हुई थी। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव सात चरणों में हुए थे। श्री खरे ने बताया कि बांग्लादेश का क्षेत्रफल 148460 वर्ग किलोमीटर और आबादी करीब 17 करोड़ है जबकि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88752 वर्ग किलोमीटर और आबादी 10 करोड़ के आसपास है। अधिक क्षेत्रफल और आबादी के बावजूद बांग्लादेश में मतपत्र के जरिए कम समय में मतदान संपन्न कराना बहुत अच्छा संदेश है।

वहां जनता के द्वारा चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना डेढ़ साल पहले सरकार का तख्तापलट होने के बाद से भारत में राजनीतिक शरण के रूप में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। उनके विरोधियों द्वारा उन पर काफी गंभीर आरोप लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में शेख हसीना की सकुशल वापसी के हालात कब बनेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है।

जुर्माने के रूप में लगा टैरिफ वापस

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारत और अमेरिका के बीच तनातनी के चलते हुआ व्यापार समझौता विलक्षण है। इससे कई नए आयाम तो आकर लेंगे ही, वह टैरिफ भी वापस होगा, जो अमेरिका ने जुर्माने के रूप में वसूला है। इस समझौते की एक और खास बात है कि भारतीय कृषि और डेयरी उद्योग की सुरक्षा और शुद्धता को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ेगी। भारत के सम्मान को बरकरार रखने वाला समझौता पहले कभी हुआ देखने सुनाने में नहीं आया। उल्लेखित इन विषयों को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक खुलासा कर चुके हैं। साफ़ है इस समझौते के बाद व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का लम्बा दौर चलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25 प्रतिशत ऊल-जलूल टैरिफ थोप दिया था। यही नहीं ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी एकतरफा निर्णय ले लिया था। यह टैरिफ भारतीय दुग्ध एवं कृषि उत्पाद हड़पने की दृष्टि से लगाया गया था। जिससे भारत दबाव में आकर इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दे। लेकिन भारत भलि-भांति जानता था कि अमेरिका के सस्ते अनाज और मांसाहारी दूध के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जाता है तो किसान तो तबाह होगा ही शाकाहारी संस्कृति को भी पलीता लगेगा। साथ ही भारत सरकार जिन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देकर कृषि और दूध उत्पादों को वैश्विक बाजार में लाने की तैयारी कर रही है, वह विचार भी चकनाचूर हो जाता। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया था कि इन क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। वैसे भी अब यह सच्चाई सामने आ रही है कि एकतरफा वैश्वीकरण से दुनिया का भला होने वाला नहीं है। अतएव स्वदेशी उत्पादों के जरिए ही आत्मनिर्भर बने रहने की पहल जारी रखनी होगी। भारत इस दिशा में मजबूती से बढ़ भी रहा है। किंतु अब भारत को अमेरिका से हुए समझौते में बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न केवल टैरिफ दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, बल्कि रूस से तेल आयात के चलते जुर्माने के रूप में वसूले गए 25 प्रतिशत टैरिफ को वापस करने का फैसला लिया है। वाइट हाउस से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फ़रवरी 2026 के बीच जिन आयात वस्तुओं पर जुर्माना लगा है, वह वापस हो जाएगा। उम्मीद बनी है कि इस छूट से भारतीय व्यापारियों को करीब 40 हजार करोड़ की राहत मिलेगी।

पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में साफ किया है कि डेयरी के सभी उत्पाद आनुवंशिक रूप से परिवर्धित उत्पाद भी समझौते से बाहर हैं। इनमें पोल्ट्री, मांस, सोयाबीन, मक्का, चावल, चीनी, गेहूं, ज्वार,बाजरा, रागी, कोदो, दाल मूंग, काबुली चना, ग्रीन टी मधु और अनेक प्रकार के फलों को बाहर रखा है। डेयरी उत्पादों में गाय-भैंस का दूध अहम है। इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। यह दूध ही है, जिससे दही, मट्ठा, मक्खन और घी जैसे सह-उत्पाद निकलते हैं। ये उत्पाद मिठाई की दुकानों से लेकर डेयरी उद्योग के जरिए करोड़ों लोगों के रोजगार का मजबूत माध्यम बने हुए हैं। लंबे समय तक गाय से पैदा बैल पर ही भारतीय कृषि निर्भर रही है। इसी कृषि की जीडीपी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से लेकर दूध पीने में दुनिया में पहले स्थान पर हैं। इसी दूध पर अमेरिकी बाजार के कब्जे के लिए अमेरिका अपने यहां उत्पादित मांसाहारी दूध बेचना चाहता रहा था।अन्य यूरोपीय देशों की निगाह भी इस दूध के व्यापार पर टिकी हैं। इस बाबत अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के व्यापार समझौते पर चली बातचीत नाकाम रही थी। क्योंकि इसमें अमेरिकन मांसाहारी दूध के उत्पाद शामिल थे। भारत सरकार ने इस बाबत दो टूक कह दिया था कि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों को भारतीय बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका और उनकी संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न है, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है।दरअसल अमेरिका चीज (पनीर) भारत में बेचने का लम्बे समय से इच्छुक था। इस चीज को बनाने की प्रक्रिया में बछड़े की आंत से बने एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इसे अत्यंत घिनौना कृत्य करके चीज में मिलाया जाता है। शाकाहारी लोग इस प्रक्रिया को देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए भारत के शाकाहारियों के लिए यह पनीर वर्जित है। गौ-सेवक व गऊ को मां मानने वाला भारतीय समाज इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका में गायों को मांसयुक्त चारा खिलाया जाता है, जिससे वे ज्यादा दूध दें। हमारे यहां गाय-भैंसें भले ही कूड़े-कचरे में मुंह मारती फिरती हों, लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता? लिहाजा अमेरिका को चीज बेचने की इजाजत इस डील में नहीं दी गई है। अकेले गुजरात में अमूल समेत 36 लाख दुग्ध उत्पादक हैं।

बिना किसी सरकारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, मठा, घी, मक्खन, पनीर, मावा आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसदी कारोबार संगठित ढांचा, मसलन डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं। 14 राज्यों की अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसदी हैं, किंतु वह दूध ही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण करके ही, मठा, घी, मक्खन, मावा, पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे आठ करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। करीब 1.5 करोड़ परिवार ही सहकारी दुग्ध उत्पादकता से जुड़े हैं, जबकि 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार आज भी सहकारिता के दायरे से वंचित हैं। दूध उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं की अहम् भूमिका रहती है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सीधे शहरी एवं कस्बाई ग्राहकों तक दूध बेचने का काम करते हैं। इसी दूध के बाजार में अमेरिका हस्तक्षेप के लिए लंबे समय से लालायित है, लेकिन उसकी दाल इस बार भी नहीं गाल पाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दस हजार नई कृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए कृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है। ऐसे में यदि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाते तो इन समितियों की मुश्किलें तो बढ़ती ही, दुग्ध उत्पादक आठ करोड़ लोगों की आजीविका पर भी संकट के बादल गहरा जाते।

जितने अधिक साधन बढ़े हैं, उतनी अधिक दुःख और दुविधा भी बढ़ी हैं: सम्भवसागर महाराज

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। मुनि श्री ने कहा कि आजकल गूगल, एआई तथा चैट जी. पी.टी, का जमाना है, कोई समस्या आई तो उसका तुरंत समाधान तो मिल जाता है, लेकिन समस्याएं बढ़ जाती है, अब तो घर में कर्मचारी की भी आवश्यकता नहीं बची। रोबोट आपके साथ काम करने तैयार है। मुनि श्री ने कहा कि यह जितने भी साधन बढ़ते जा रहे है, उससे आपको सुख मिलेगा? तो सुनो यह सुख नहीं वल्कि भविष्य में आपको दुःख ही प्रदान करने वाले है, "संसार क्षणभंगुर है",यंहा पर कोई भी वस्तु शास्वत नहीं है। आप भले ही बहूत अच्छा बंगला खरीद लो बहुत अच्छी गाड़ी ले आओ आपके सभी परिवार जन पत्नी,पति, बेटा बेटी सभी बहूत अच्छे है लेकिन ध्यान रखना यह कोई भी स्थाई नहीं है" कल तक जो वस्तु अच्छी थी वही वस्तु आज खराब हो जाती है। जिस शरीर के लिये आप इतनी अधिक भागदौड़ कर रहे हो,वह शरीर भी आपका साथ छोड़ने वाला है, आप लोग रोज रोज पूजा में पढ़ते भी है"जिसके श्रृंगारों में यह मेरा महंगा जीवन घुल जाता" यह शरीर ही दगाबाज हैं, जो आपका साथ छोड़ देता है,तो आप किस वस्तु को स्थाई मान रहे है?

नरसिंहपुर में 300 किसानों का 7 करोड़ गन्ना भुगतान अटका: भारतीय किसान यूनियन ने कहा- अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने महाकोशल शुगर मिल के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मणिंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। बताया गया कि लगभग 300 किसानों का करीब 7 करोड़ रुपये बकाया है। किसानों का कहना है कि मिल ने पूरे सीजन गन्ने की तुलाई तो कर ली, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। पेमेंट अटकने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनके पास घर खर्च तक के पैसे नहीं बचे हैं। कायदे के अनुसार गन्ना बेचने के 14 दिन के भीतर भुगतान मिल जाना चाहिए। देरी होने पर मिल को ब्याज भी देना पड़ता है, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी की जा रही है।

मालिक विदेश में, किसान परेशान

यूनियन ने आरोप लगाया है कि मिल मालिक किसानों का पैसा दिए बिना विदेश में मौज कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मिल मालिकों के पासपोर्ट जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत किसानों का भुगतान कराया जाए।

बड़े आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और मिल प्रबंधन की होगी।

श्री खाटू श्याम जी मंदिर का भव्य भूमि पूजन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। "हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा" के जयघोष के साथ ग्राम नौसर में भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिला। जहां करताना टिमरनी रोड पर स्थित नौसर में प्रस्तावित श्री खाटू श्याम जी मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ 'भव्य भूमि पूजन' के साथ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया।

हजारों भक्तों की उपस्थिति में हुआ शिलान्यास

(फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया) को सुबह 9 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। इस पावन अवसर पर टिमरनी क्षेत्र सहित दूर-दराज के गाँवों से आए हजारों श्याम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

श्रद्धा और सहयोग से बनेगा मंदिर

आयोजन समिति ने बताया कि यह मंदिर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि श्याम भक्तों की अटूट श्रद्धा और सहयोग का प्रतीक होगा। मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। लोगों का मानना है कि इस मंदिर के बनने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान भूमि पूजन के पश्चात विशाल भंडारे और महाप्रसादी का आयोजन के साथ बाबा के भजनों की भी प्रस्तुति दी गई। हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद स्वरूप प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय युवाओं और भक्तों की टोली सक्रिय रही। "करने वाला भी श्याम, कराने वाला भी श्याम" इसी भाव के साथ उपस्थित जनसमुदाय ने मंदिर निर्माण के इस पुनीत कार्य में तन-मन-धन से सहयोग करने का संकल्प लिया।

छोटी नदियां बचाओ, बड़ी नदियां संवरेगी

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हमारी विशाल नदियाँ जीवन का आधार हैं, पर उनकी धमनियाँ जो छोटी नदियाँ हैं सूख रही हैं। बिना इनकी रक्षा के बड़े संरक्षण प्रयास मात्र दिखावा बनकर रह जाते हैं। छोटी नदियाँ भूजल रिचार्ज करती हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और बाढ़ रोकती हैं। प्रदूषण, अतिक्रमण और लापरवाही ने इन्हें मृतप्राय बना दिया है। जलवायु परिवर्तन का पहला शिकार यही छोटी धाराएँ हैं, जो अब रेगिस्तान में बदल रही हैं। सम्पूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्याधिक महत्त्व रहा है। इसलिए भारत में नदियों को मां कह कर पुकारा गया। यह उस दौर की बात है जब लोगों के दिन की शुरुआत नदियों के तट से शुरू होती थीं। प्राचीन काल से ही नदियां मां की तरह हमारा भरण - पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं रचती हैं, बस्तियां बस्ती हैं। मगर जब इंसान की जरूरत का जल नलों के जरिए घरों तक पहुंच गया तो नदियां क्या नदी, झील और कुएं आदि अपने महत्व खोने लगे। चुकी नदियों के जल के उपयोग से पुण्य और सुखों की प्राप्ति की मान्यता जुड़ी हुई है इसलिए इंसान नदियों से जुड़े अनुष्ठानों के प्रति तो जागरूक रहा लेकिन नदियों के प्रवाह के सुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे नदियां दुर्दशा की शिकार होने लगीं। सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार छोटी नदियां हुईं। चुकी उनकी प्रवाह क्षेत्र कम था इसलिए उपेक्षा ने उन्हें नालों में बदल दिया। छोटी नदियों की दूरदर्शा के कारण ही बड़ी नदियों के जलप्रवाह में कमी आई है। गंगा, यमुना, जैसी बड़ी नदियों को स्वच्छ रखने पर तो बहुत काम हो रहा है पर ये नदियां बड़ी इसी लिए बनती है क्योंकि इनमें बहुत से छोटी नदियां आ कर मिलती हैं। एक अनुमान है कि आज भी देश में कोई बारह हजार छोटी ऐसी नदियां है, जो उपेक्षित है, उनके अस्तित्व पर खतरा है। उन्नीसवीं सदी तक बिहार में कोई 6000 नदियां हिमालय से उतर कर आती थी, आज इनमें से महज 400 से 600 का ही अस्तित्व बचा है। मधुबनी, सुपौल में बहने वाली तिलयुगा नदी कभी कोसी से भी विशाल हुआ करती थी, आज उसकी जल धरा सिमट कर कोसी की सहायक नदी के रुप में रह गई है। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी को तो सरकारी इमारतें ही चाट गई। नदियों के इस तरह रूठने और उससे बाढ़ और सुखाड़ के दर्द साथ साथ चलने की कहानी देश के हर जिले और कस्बे की है। मध्य प्रदेश की दूधी नदी को तो कुछ समय पहले बारहमासी नदी माना जाता था लेकिन अब इसका जलस्तर बहुत नीचे जा चूका है। सतपुड़ा के मछवासा, आंजन ओल, पलकमती और कोरनी नदी की हालत अच्छी नहीं है। सहारनपुर की पांवधोई नदी गंदे नाले में बदल गई थी लेकिन लोगों की जागरूकता ने बुरी हालत से मुक्त कराने में सफलता पाई है पर काली हिंडन और गुनता आदि नदियां अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही है। छोटी नदी केवल पानी के आवागमन का साधन नही होती। उसके चारों तरफ समाज भी होता हे और पर्यावरण भी। नदी के किनारे किसान भी हैं और मछुआरा भी। छोटी नदियों के सेहत बिगड़ने पर तालाब से लेकर कुएं तक में जल का संकट आता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से समाज में ऐसा कोई वर्ग नही है जो इससे प्रभावित नही हुआ हो। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में छोटी नदियां धरती के तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी की नमी बनाए रखने और हरियाली के संरक्षण के लिए अनिवार्य है। नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने से, उसमे से बालू रेत उत्खनन को नियंत्रित करने, नदी की गहराई के लिए उसकी समय समय पर सफाई से इन नदियों को अपना मानकर सहेजने लगे तो इससे पर्यावरण के साथ समाज के लिए भला होगा। धीरे धीरे हमारी सभ्यता एक बड़े जल संकट की ओर तेजी से बढ़ रहीं है। अगर वक्त रहते हम नही जागे तो बड़ी मुसीबत से घिर जायेंगे। छोटी नदियां बचेंगी तब ही हम बड़ी नदियों को बचा पाएंगे। इसके बिना नदी संरक्षण की कोशिशें अधूरी रह जायेंगी।

भगोरिया: मिट्टी की महक से सजा सांस्कृतिक कुंभ

"संस्कृति वो जड़ है जो हमें तूफानों में भी खड़ा रखती है,
और उत्सव वो टहनी है जिस पर खुशियों के फूल खिलते हैं।"

फाल्गुन की हवाओं में जब पलाश के सुर्ख फूलों की मादक गंध घुलने लगती है और खेतों में गेहूँ की बालियाँ सुनहरी होकर झूमने लगती हैं, तब आदिवासी क्षेत्रों की पहाड़ियों में एक अलग ही संगीत गूँजने लगता है। यह संगीत है—भगोरिया का। भगोरिया केवल एक लोक-उत्सव नहीं है; यह मालवा और निमाड़ के आदिवासी समाज के स्वाभिमान, उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति उनके अगाध प्रेम का जीवंत घोषणापत्र है। यह उत्सव बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जड़ों की ओर लौटने का आनंद ही कुछ और है।

परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व

आज के दौर में जब हम भगोरिया को देखते हैं, तो एक तरफ पारंपरिक मांदल की थाप है और दूसरी तरफ आधुनिकता का शोर। करीब चार दशक पहले मेरी पुलिस विभाग की पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी, तब से अब तक परिदृश्य बहुत बदला है। जहाँ कभी प्रकृति की प्रधानता होती थी, वहाँ अब बाजारवाद का रंग भी चढ़ने लगा है। मेलों में अब केवल ढोल-ताशे नहीं, बल्कि लाउडस्पीकरों पर बजते फिल्मी गीत और ब्रांडेड कपड़ों की चमक भी दिखाई देती है। लेकिन, इस बदलाव के बीच सबसे सुखद पहलू यह है कि इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का बीड़ा खुद आदिवासी समाज ने उठाया है। युवाओं के हाथों में आज स्मार्टफोन भले ही हों, लेकिन उनके पैरों में थिरकन आज भी उसी 'मांदल' की लय पर आती है जो उनके पूर्वजों की थी। यह उनकी अपनी पहचान को बचाए रखने की एक मौन लेकिन सशक्त क्रांति है।

स्मृतियों के झरोखे से: चार दशक का सफर

मेरी स्मृतियाँ मुझे करीब चार दशक पीछे ले जाती हैं। पुलिस सेवा में प्रवेश के ठीक बाद मेरी पहली पोस्टिंग आदिवासी अंचल झाबुआ में हुई थी। वह एक ऐसा दौर था जब प्रशासनिक जिम्मेदारियों की तुलना में मुझे इस अंचल की जीवन-शैली को समझना ज्यादा चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगा। खाकी वर्दी पहनकर जब मैं पहली बार भगोरिया की व्यवस्था संभालने पहुँचा, तो मैं दंग रह गया। वहाँ कानून नहीं, बल्कि लोक-परंपरा का अनुशासन था। वह जीवंतता, वह निश्छल मुस्कान और सांस्कृतिक गरिमा आज भी मेरी आँखों में उतनी ही ताजा है, जितनी उस समय थी।

रंगों से पहले उमंग का उत्सव

भगोरिया का आयोजन होली से ठीक सात दिन पहले शुरू होता है। यह वह समय है जब रबी की फसल कटकर घर आ चुकी होती है और किसान के पास अपनी मेहनत का जश्न मनाने का वक्त होता है। साप्ताहिक हाटों के रूप में लगने वाले ये मेले किसी बड़े सांस्कृतिक कुंभ से कम नहीं होते।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

"जहाँ रूह नाचती हो, वहाँ पैरों को संगीत की जरूरत नहीं होती।"

दूर-दराज के गाँवों से युवक-युवतियाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर टोलियों में निकलते हैं। चांदी के हंसली, कड़े और बोर जैसे आभूषणों से लदी युवतियाँ और सिर पर साफा बाँधे हाथ में तीर-कमान या बाँसुरी लिए युवक—यह दृश्य किसी महान कलाकार की पेंटिंग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पहनावा केवल शरीर ढंकने का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली हिस्सा है।

प्रेम, मर्यादा और सामाजिक स्वीकृति

भगोरिया की सबसे चर्चित और अक्सर गलत समझी जाने वाली परंपरा है—जीवनसाथी का चुनाव। लोग इसे 'भागने' का मेला कहते हैं, लेकिन असल में यह 'चुनने' और 'स्वीकारने' की एक बेहद खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था है। परंपरा के अनुसार, यदि कोई युवक किसी युवती को 'पान' भेंट करता है और युवती उसे स्वीकार कर लेती है, तो यह उनके आपसी प्रेम का मूक संकेत होता है। कई जगहों पर गुलाल लगाने की भी परंपरा है। यह प्रेम की वह सहज और सार्वजनिक स्वीकृति है। इसके बाद होने वाले सामाजिक रीति-रिवाज उनके रिश्ते को विवाह की पवित्रता में बदल देते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रेम में जबरदस्ती नहीं, बल्कि आपसी सहमति की खुशबू होनी चाहिए।

ऐतिहासिक गौरव गाथा

लोक श्रुतियों के अनुसार, भगोरिया का इतिहास राजा भोज के समय से जुड़ा है। माना जाता है कि दो भील राजाओं, कासूमार और बालून ने भागोर नामक स्थान पर इस मेले की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे यह परंपरा आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और 'भागोरिया' के नाम से अमर हो गई। ऐतिहासिक प्रमाण चाहे जो भी कहें, लेकिन भील समाज के लिए यह उनकी वीरता और पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम भी है।

बदलते दौर की नई चुनौतियां

आज जब हम 2026 के पायदान पर खड़े हैं, भगोरिया के सामने कई चुनौतियां हैं। सेल्फी संस्कृति और सोशल मीडिया के प्रभाव ने मेलों की निजता को थोड़ा प्रभावित किया है। बाजारी ताकतों ने स्वदेशी हाटों की जगह प्लास्टिक और बनावटी वस्तुओं को बढ़ावा दिया है। किंतु, प्रशंसा करनी होगी उस आदिवासी युवा की, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने और शहरों में नौकरी करने के बावजूद, भगोरिया के इन सात दिनों में अपने गाँव लौट आता है। वह कोट-पैंट उतारकर अपनी पारंपरिक पोशाक पहनता है और मांदल की थाप पर पूरी शिद्दत से थिरकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जड़ें अभी भी गहरी हैं।

एक साझा विरासत

भगोरिया केवल आदिवासियों का पर्व नहीं है, यह समूचे भारत की सांस्कृतिक विविधता का गौरव है। यह हमें याद दिलाता है कि विकास का अर्थ अपनी पहचान खोना नहीं है। "मिट्टी से जुड़ाव ही इंसान को आसमान छूने की ताकत देता है।" प्रशासन और नागरिक समाज का यह दायित्व है कि हम इस उत्सव की मौलिकता को बचाए रखें। हमें पर्यटन के नाम पर इसे 'तमाशा' बनने से रोकना होगा और इसकी सांस्कृतिक शुचिता को बनाए रखना होगा। जब भी फाल्गुन की हवा में रंगों की आहट होती है, मुझे झाबुआ की वे पगडंडियाँ याद आती हैं। भगोरिया जीवन का वह राग है, जो हमें सिखाता है कि अभावों में भी कैसे भरपूर जिया जाता है। यह उत्सव है साहस का, सामूहिकता का और उस चिरंतन प्रेम का जो सदियों से इस मिट्टी में बसा है।

प्रगतिशील युवा विकसित छत्तीसगढ़

खेल प्रोत्साहन योजना लागू, ओलंपिक विजेताओं के लिए ₹1-3 करोड़ का पुरस्कार और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास

सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, लगभग 32,000 पदों पर भर्ती

नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 7.96 एकड़ भूमि आवंटित

160 आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु ₹484 करोड़ स्वीकृत

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना

34 नगरीय निकायों में "नॉलेज बेस्ड सोसाइटी" हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल

R.O. No. : 13673/ 1

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)